

प्रेषक,

प्रदीप सिंह शक्ती
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 26 मार्च, 2008

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-08 में श्री राज्यपाल आवास, सचिवालय, ऑडिटोरियम हेतु विद्युत संबंधी 04 कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सधिव श्री राज्यपाल के पत्र सं0-2953/जी0एस0/C-104/2008 दिनांक 22-02-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल आवास, सचिवालय, ऑडिटोरियम हेतु विद्युत संबंधी 04 कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रुपये 112.80 लाख पर टी.ए. सी वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 109.81 लाख (रुपये एक करोड़ नौ लाख इक्कासी हजार मात्र) की धनराशि की संलग्न सूची के कॉलम-4 में अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 109.81 लाख (रुपये एक करोड़ नौ लाख इक्कासी हजार मात्र) की धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम परीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्न है, स्वीकृत नार्न से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
6. एकमुस्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
8. आगणन में ली गई नदों की आपूर्ति वृहद प्रचर-प्रसार के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर ही जायें।
9. आगणन में जिन नदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी नद में किया जाय, एक नद का दूसरी नद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य स्वयं प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीकृत आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे सगस्त वस्तुओं को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
 13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
 14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अभिशास्त्री अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 15. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्हीं अन्य वस्तु से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
 16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-07 लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत खर्चव्यय-80 सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य भवन-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं-01-12 में वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
 17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.- 289/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- सलग्नक:- 04 कार्यों की सूची।

भवदीय,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या- 536
(1)/11(2)/08-15(प्रा.आ)/07, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोनिवि, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 11 वीं वृत्त वि०/या० लो०नि०वि० देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या- ४३६ / 111(2)/08-15(प्रा.आ)/07, दिनांक २८ मार्च, 2008 का संलग्नक सूची।

क्र.सं०	कार्य का नाम	(घनराशि रुपये लाख में)	
		अनुमानित लागत	टी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित घनराशि
1	2	3	4
01-	श्री राज्यपाल ऑडिटोरियम, सचिवालय तथा निवास में कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं ई०सी०ए०सी०ए०एस० सिस्टम का कार्य।	42.35	41.39
02-	श्री राज्यपाल सचिवालय ऑडिटोरियम, सचिवालय भवन में स्टेज लाईट सिस्टम एवं साउन्ड सिस्टम का कार्य।	28.83	27.65
03-	राजभवन परिसर में ऑडिटोरियम, सचिवालय भवन में 320 क्वेरी०ए० क्षमता का छत्ती संहिता डी०सी० सेंट की स्थापना का कार्य।	26.12	25.52
04-	राजभवन सचिवालय में 7 चैलेंजर अग्रेस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन (एम०आर०एल०) एलीवटर लगाने का कार्य।	15.50	15.25
योग-		112.80	109.81

(रुपये एक करोड़ नौ लाख इक्कासी हजार मात्र)

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव

८